भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 272

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

2 श्रावण, 1946 (शक)

डिजिटल इंडिया पहल की स्थिति

272. श्री सी. एन. अन्नादुरई :

श्री नवसकनी के. :

श्री जी. सेल्वम :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा उसका उपयोग किया गया;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने लोगों के सशक्तीकरण में डिजिटल इंडिया पहल की भूमिका का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत परिणाम क्या हैं;

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में ग्रामीण जनता द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने की सीमा को मापने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे और परिणाम क्या हैं; और

(छ) तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों में डिजिटल पहुंच तथा ई-सरकारी टूल्स के उपयोग में कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) सरकार ने डिजिटल सुलभता, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके और डिजिटल अंतर को पाटकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम तीन प्रमुख दृष्टि क्षेत्रों पर केंद्रित है, अर्थात् प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा, मांग पर शासन और सेवाएं, और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। समग्र लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुधार करें, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार करें और भारत में निवेश और रोजगार के अवसर और डिजिटल तकनीकी क्षमताएं पैदा करें।

तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने और जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं / परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । तमिलनाडु राज्य में ऐसी डिजिटल सुविधाओं में लगभग 18,373 कार्यात्मक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना के तहत राज्य के 38 जिलों में से प्रत्येक में स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन

जागरूकता और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं प्रदान करना, ई-जिला मिशन मोड परियोजना के तहत 134 से अधिक नागरिक-केंद्रित ई-सेवाएं शुरू करना और कार्यात्मक डिजिटल साक्षरता के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के तहत 10.69 लाख लोगों को प्रमाणित करना शामिल है। इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य सहित देश भर के नागरिकों को भी विभिन्न पहलों जैसे कि न्यू-एज गवर्नेंस के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिलॉकर, ई-साइन, ई-हॉस्पिटल और माईगोव, माईस्कीम आदि के तहत ई-सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया गया है।

(ख): डिजिटल इंडिया एक व्यापक कार्यक्रम है जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की कई परियोजनाओं को कवर करता है। प्रत्येक परियोजना की अपनी बजटीय आवश्यकता होती है और तदनुसार कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालय/विभागों द्वारा परियोजना-योजना तैयार की गई है और संबंधित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बजट ब्यौरे रखे जा रहे हैं। हालांकि, पिछले तीन वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा आबंटित और उपयोग किया गया बजट निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	आबंटित बजट (करोड़ रुपए में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपए में)
2021-22	6,388.00	4,504.36
2022-23	5400.50	3863.13
2023-24	5354.51	3945.42

(ग) और (घ): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, सभी प्रमुख योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन आम तौर पर एक स्वतंत्र तीसरे पक्षकार के माध्यम से किया जाता है, जो निष्पक्ष स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए योजना के कार्यान्वयन में शामिल नहीं है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन अक्टूबर, 2020 में सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स (सीआईपीएस), हैदराबाद के माध्यम से आयोजित किया गया था। अध्ययन से पता चला है कि डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित सूचना तक पहुंच प्रदान करके, सरकार और नागरिकों के बीच विभिन्न प्रणालियों और सेवाओं को एकीकृत करके नागरिक सेवाओं के स्वरुप को बदल रहा है, जिससे नागरिकों के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मूल्यों को सशक्त और बेहतर बनाया जा रहा है ।

(ङ) से (छ): ई-ताल प्लेटफॉर्म (https://etaal.gov.in/) पर ई-लेन-देन के आंकड़े भारत में ई-सरकारी उपकरणों के डिजिटल प्रसार और उपयोग में वृद्धि का संकेत देते हैं। वर्ष 2023 के दौरान 4,209 ई-सेवाओं के लिए ई-ताल प्लेटफॉर्म पर 21,224 करोड़ से अधिक ई-लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जबकि वर्ष 2022 के दौरान 4,020 सेवाओं के लिए 15,810 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान ई-ताल प्लेटफॉर्म पर रिकार्ड किए गए ई-लेन-देन की संख्या निम्नानुसार है।

राज्य	**ई-लेनदेन की संख्या (करोड़ में)**		
	2021	**2022**	**2023**
तमिलनाडु	32.79	44.56	60.00

****